

# INVESTMENT AVENUES®

## इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज

भोपाल, शनिवार 03 से 09 जनवरी 2026 भोपाल, मध्यप्रदेश से प्रकाशित वर्ष- 13 अंक-73 पृष्ठ- 8 मूल्य- रु. 5 /-

### 2025 में भारत ने जापान को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का ताज पहना

दूसरी तिमाही में महंगाई 0.71% पर, बेरोजगारी दर में गिरावट; मजबूत घरेलू मांग और निर्यात से GDP ग्रोथ 7.8%

**नई दिल्ली:** वर्ष 2025 भारत के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ, जब देश ने जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल कर लिया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत का नाममात्र GDP \$4.2 ट्रिलियन पहुंच गया, जबकि जापान \$4.1 ट्रिलियन पर रुका। यह उपलब्धि मजबूत घरेलू मांग, निर्यात वृद्धि और नीतिगत सुधारों का परिणाम है।

दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2025) में महंगाई दर घटकर 0.71% पर आ गई, जो दो दशकों में सबसे कम है। RBI की सख्त मौद्रिक नीति और अच्छी फसल से खाद्य कीमतें नियंत्रित रहीं। बेरोजगारी दर भी 6.8% से घटकर 5.9% हो गई, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में MNREGA और कृषि रोजगार से सुधार हुआ।

Q2 में GDP वृद्धि 7.8% रही, जो सेवा क्षेत्र (IT-ITES) और मैन्युफैक्चरिंग से प्रेरित थी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, यह उपलब्धि प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत' विजन का प्रमाण है। हम 2030 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि PLI स्कीम, इंफ्रा निवेश और FDI (80 अरब डॉलर) से यह संभव हुआ। हालांकि, वैश्विक मंदी और व्यापार तनाव चुनौती बने हुए हैं।

2025 में शेयर बाजार ने निफ्टी 25,000 और सेंसेक्स 85,000 पार किए। रुपया 89-90 के दायरे में स्थिर रहा। यह वर्ष भारत के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक बना। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2026 में 7.5% ग्रोथ के साथ भारत जापान से और दूर निकलेगा।



### उद्योग वर्ष 2025: मध्यप्रदेश उद्यमिता और निवेश का नया हब

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में निवेश और रोजगार का रिकॉर्ड वर्ष

**भोपाल:** वर्ष 2025 मध्यप्रदेश के लिए औद्योगिक और उद्यमिता विकास का ऐतिहासिक वर्ष साबित हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य ने निवेश आकर्षण, नीतिगत सुधारों और स्टार्टअप-एमएसएमई को बढ़ावा देकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। राज्य को 'उद्योग एवं रोजगार वर्ष' घोषित कर सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया कि विकास की धुरी अब उद्योग और उद्यमिता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' संकल्प को साकार करने में मध्यप्रदेश ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि रही 'इन्वेस्ट मध्यप्रदेश - ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025'। फरवरी में भोपाल में आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन में 26.61 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो क्षेत्रीय कॉन्क्लेव और अंतरराष्ट्रीय रोड शो सहित कुल 30.77 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गए। इन प्रस्तावों से 21 लाख से अधिक रोजगार सृजन की उम्मीद है। समिट में 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, 200 से ज्यादा सीईओ और यूनिकॉर्न संस्थापकों ने भाग लिया। नवीकरणीय ऊर्जा में 5.72 लाख करोड़, पर्यटन, आईटी, फार्मा और टेक्सटाइल जैसे सेक्टरों में भारी निवेश आकर्षित हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे 'विकसित भारत' का ग्रोथ इंजन बताया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 18 नई औद्योगिक नीतियां लागू कीं, जिनमें इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2025, टेक्सटाइल पॉलिसी, सेमीकंडक्टर और स्पेस टेक पॉलिसी शामिल हैं। इनसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार हुआ और राज्य टॉप अचीवर स्टेट बना। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जैसे राइज 2025 (रतलाम) और अन्य आयोजनों से क्षेत्रीय विकास को बल मिला। रतलाम में 858 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और 2,419 करोड़ के लोन वितरण से हजारों युवाओं को रोजगार मिला।

एमएसएमई क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई। एक वर्ष में रिकॉर्ड 4.57 लाख नई यूनिट्स पंजीकृत हुईं, कुल 20.43 लाख यूनिट्स हो गईं। एमएसएमई समिट 2025 में 200 करोड़ की सहायता और 80 से अधिक स्टार्टअप्स को फंडिंग दी गई। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से लाखों उद्यमियों को लाभ पहुंचा। स्टार्टअप पॉलिसी 2025 से महिलाओं और ग्रामीण उद्यमियों को प्रोत्साहन मिला, राज्य में स्टार्टअप्स की संख्या तेजी से बढ़ी।

डॉ. यादव ने विदेशी दौड़ों और रोड शो से निवेश आकर्षित किया। कोलकाता में 14,600 करोड़, अन्य शहरों में हजारों करोड़ के प्रस्ताव आए। अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट में 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स

की आधारशिला रखी गई। राज्य में बिजली अधिशेष, सस्ती भूमि और कुशल श्रमबल से निवेशक आकर्षित हुए।

वर्ष 2025 ने साबित किया कि डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश अब निवेश और उद्यमिता का प्रमुख केंद्र बन चुका है। यह विकास यात्रा 2026 में कृषि आधारित उद्योगों के साथ और गति पकड़ेगी, जिससे 'विकसित मध्यप्रदेश' का सपना साकार होगा।



### AC-फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान 10% तक महंगे हो सकते हैं

BEE के नए स्टार रेटिंग नियम आज से लागू, ऊर्जा दक्षता पर सख्ती; कॉपर कीमतों में उछाल से लागत बढ़ी

**नई दिल्ली:** नए साल की शुरुआत के साथ उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है, क्योंकि एयर कंडीशनर (AC), रेफ्रिजरेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतें 10% तक बढ़ सकती हैं। इसका मुख्य कारण ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) के नए स्टार रेटिंग नियम हैं, जो आज से लागू हो गए हैं। इन नियमों से निर्माताओं को अधिक ऊर्जा कुशल उत्पाद बनाने पड़ेंगे, जिससे उत्पादन लागत बढ़ेगी।

BEE ने AC और फ्रिज के लिए न्यूनतम 3-स्टार रेटिंग अनिवार्य की है, जबकि पहले 1-स्टार मॉडल्स भी बिकते थे। नए मानकों में ISEER (Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio) को सख्त किया गया है, जिससे पुराने मॉडल्स बाजार से बाहर हो जाएंगे। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि नई तकनीक जैसे इन्वर्टर कॉम्प्रेसर और बेहतर इंसुलेशन की जरूरत से लागत 5-8% बढ़ेगी।

इसके अलावा, वैश्विक बाजार में कॉपर की कीमतों में 20% उछाल ने स्थिति बिगाड़ी है। AC और फ्रिज में कॉपर कॉइल्स का बड़ा उपयोग होता है, जिससे लागत में अतिरिक्त 2-3% इजाफा हुआ। वोल्तास, LG, सैमसंग और दायकिन जैसी कंपनियों ने पहले ही 5-10% कीमत वृद्धि की घोषणा की है।

विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय में ये नियम उपभोक्ताओं को बिजली बिल में बचत देंगे, लेकिन शुरुआती कीमत बढ़ोतरी मध्यम वर्ग को प्रभावित करेगी। सरकार का लक्ष्य 2030 तक ऊर्जा खपत 20% कम करना है। उपभोक्ता अब 5-स्टार मॉडल्स पर फोकस करें तो लंबे समय में फायदा होगा। बाजार में नए मॉडल्स की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है।



## जेन जूमर्स की म्यूचुअल फंड्स से बढ़ती मोहब्बत: SIP से निवेश का नया ट्रेंड

18-25 आयु वर्ग में SIP अकाउंट्स 40% बढ़े, डिजिटल प्लेटफॉर्म और फाइनेंशियल लिटरेसी का कमाल; 2030 तक युवा निवेशकों का AUM 30 लाख करोड़ पार करने का अनुमान

**नई दिल्ली:** जेनरेशन Z (जेन जूमर्स), जो 1997 से 2012 के बीच जन्मे हैं, भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का नया चेहरा बन रहे हैं। AMFI के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 18-25 आयु वर्ग में SIP अकाउंट्स पिछले दो वर्षों में 40% बढ़कर 1.5 करोड़ हो गए हैं। युवा निवेशक डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे Groww, Zerodha Coin और Paytm Money के जरिए आसानी से निवेश कर रहे हैं।

यह ट्रेंड सोशल मीडिया, फिनफ्लूएंसर्स और फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन से प्रेरित है। जेन जूमर्स इक्विटी, हाइब्रिड और इंडेक्स फंड्स में रुचि दिखा रहे हैं, जहां औसत SIP राशि 2,500-5,000 रुपये मासिक है। विशेषज्ञों का कहना है कि महंगाई, जॉब अनिश्चितता और

जल्दी रिटायरमेंट की चाहत ने युवाओं को निवेश की ओर धकेला है। AMFI के CEO वेंकट चालासानी ने कहा, जेन Z डिजिटल नेटिव है, जो रिसर्च कर निवेश करता है। उनका योगदान इंडस्ट्री के AUM को 70 लाख करोड़ तक ले जाएगा। 2025 में युवा निवेशकों का हिस्सा 25% पहुंच गया, जो 2020 में 10% था। लड़कियां भी 35% हिस्सेदारी ले रही हैं।

हालांकि, विशेषज्ञ चेतावते हैं कि मार्केट वोलैटिलिटी से युवा प्रभावित हो सकते हैं। SEBI की फाइनेंशियल एजुकेशन पहल ने जोखिम समझ बढ़ाई है। 2030 तक युवा निवेशकों का AUM 30 लाख करोड़ पार करने का अनुमान है। यह ट्रेंड भारत की वेल्थ क्रिएशन स्टोरी को नई

पीढ़ी से जोड़ रहा है। जेन जूमर्स की यह मोहब्बत म्यूचुअल फंड्स को लंबी उड़ान देगी।



## Ceigall India Secures Rs 1,000+ Cr Mega Infra Project in Madhya Pradesh

**EPC Giant to Build Elevated Corridor in Bhopal; Boosts Order Book to Rs 15,000 Cr Amid State's Infrastructure Push**

**Bhopal:** Ceigall India Limited, a leading engineering, procurement, and construction (EPC) firm, has bagged a prestigious infrastructure project worth over Rs 1,000 crore in Madhya Pradesh. The contract, awarded by the Madhya Pradesh Road Development Corporation (MPRDC), involves constructing an elevated corridor in Bhopal to ease urban congestion and enhance connectivity.

The project, part of the state's ambitious urban mobility plan, includes a multi-lane elevated structure spanning key arterial roads, flyovers, and interchanges. Expected to be completed in 36 months, it will significantly reduce travel time in the capital and support the growing traffic from commercial hubs.

This win reinforces our strong execution capabilities in complex urban infrastructure, said Ramneek Sehgal, Managing Director, Ceigall India. The company, known for highways, bridges, and metro projects, now has an order book exceeding Rs 15,000 crore, with Madhya Pradesh contributing substantially.

The award aligns with Madhya Pradesh's Rs 1 lakh crore infrastructure pipeline under the 'Abhyudaya Madhya Pradesh' vision, focusing on Tier-2 cities like Bhopal, Indore, and Gwalior. Analysts estimate the project will create 2,000 direct jobs and stimulate ancillary industries.

Ceigall's shares surged 4.5% to Rs 420 on BSE following the announcement, reflecting investor optimism. With a robust bid pipeline of Rs 50,000 crore, the firm is poised for 25% revenue growth in FY26.

As India targets world-class urban infrastructure, Ceigall's Madhya Pradesh foray underscores the state's emergence as a key EPC destination, driving economic momentum and sustainable development.



## MIRACLE IS REAL

But, can you count on it all the time?



Want to choose the right policy? Connect with me!



Vision Invest Tech Private Limited

ARN: 10613 | AMFI Registered Mutual Fund Distributor

(+91)7389912025 visionadvisorymkt@gmail.com



Sh. Pradeep Karambelkar  
Founder & Editor



Dr. Irshad Ahmad Khan  
Sub-Editor



Sh. Pushpendra Singh  
Marketing Officer



## Green Energy & EV Ecosystem: India's Clean Energy Push Till 2026

India is rapidly moving toward a clean energy future, driven by renewable power growth and the rising popularity of electric vehicles (EVs). With global pressure to cut carbon emissions and domestic goals to reduce dependence on fossil fuels, the green energy and EV ecosystem is now one of the most talked-about themes on the Indian stock market. As we head into 2026, this sector is expected to benefit both the economy and long-term investors.

According to the International Energy Agency (IEA), India aims to achieve 500 GW of renewable energy capacity by 2030, up from about 175 GW in 2025. This ambitious plan includes solar, wind, small hydro, and bioenergy, and is part of India's commitment to climate action. The government has also pledged that 50% of electricity will come from clean energy sources by 2030. These targets have given a strong boost to green energy companies.

The uptake of solar energy has been particularly strong. India's total installed solar capacity has crossed 70 GW and is expected to reach 100 GW by 2026. This expansion supports not only utility-scale solar farms but also rooftop solar systems for homes, businesses, and industries. Growing investments in renewable energy are attracting both private companies and foreign capital, and this trend is reflected in the stock market.

Renewable power producers like Adani Green Energy and Tata Power Renewable Energy Ltd. (TREPL) have seen strong

interest from investors. Stocks of renewable energy companies have delivered solid returns over the past few years, driven by rising capacity additions and long-term power purchase agreements (PPAs). Energy ETFs and thematic funds that focus on sustainability have also gained traction among Indian investors.

Electric vehicles are another major pillar of India's clean energy transformation. In 2024, EV sales in India crossed 1.5 million units, up from around 850,000 units in 2023, showing a near doubling year-on-year. According to Bloomberg NEF, India's EV adoption rate is expected to reach 15-20% of total vehicle sales by 2026, with electric two-wheelers and three-wheelers leading the way. The push for electric cars is supported by incentives under the FAME-II (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles) scheme and production-linked incentive (PLI) schemes for EV components and battery systems.

Indian companies like Tata Motors, Mahindra & Mahindra, and TVS Motor are expanding their EV portfolios. Tata Motors' electric cars including the popular Tata Nexon EV have gained significant market share, while TVS and Bajaj are growing electric two-wheeler adoption. As demand for EVs rises, related companies such as Battery Maker Exide Industries and Amara Raja Batteries are also attracting investor attention.

An important part of the EV ecosystem is charging infrastructure. The number of public charging stations in India crossed

6,000 in 2025 and is expected to exceed 15,000 by 2026 as companies like Tata Power and E-Vehicle charging network operators expand their footprint. This expansion supports not only electric cars but also buses and commercial EV fleets.

For stock market investors, the green energy and EV theme is becoming one of the most talked-about sectors. Funds and ETFs with exposure to renewable energy and EV supply chains offer diversified ways to participate in India's long-term clean energy transition. However, investors should also be cautious, as the sector can be volatile and influenced by policy changes and commodity pricing.

In simple terms, India's green energy and EV ecosystem is no longer a future idea it is happening now, backed by strong government support, corporate participation, and growing consumer demand. As the nation marches toward 2026, this clean energy revolution is likely to continue powering both sustainable growth and investment opportunities on Dalal Street.

Dr. Irshad Ahmod  
Khan  
Sub-Editor



### टाटा पावर और बंगाल चैंबर का समझौता: राज्य में MSMEs के बीच रूफटॉप सोलर को बढ़ावा

10,000 MSMEs को सोलर अपनाने का लक्ष्य, बिजली बिल में 50% बचत; हरित ऊर्जा और रोजगार सृजन पर फोकस

**कोलकाता:** टाटा पावर की सहायक कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (TPREL) ने बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य पश्चिम बंगाल में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के बीच रूफटॉप सोलर अपनाने को तेज करना है। यह साझेदारी राज्य के MSME सेक्टर को हरित ऊर्जा की ओर ले जाएगी।

समझौते के तहत अगले तीन वर्षों में 10,000 MSMEs को रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य है। टाटा पावर सोलर पैनल्स, इन्वर्टर और इंस्टॉलेशन प्रदान करेगी, जबकि बंगाल चैंबर जागरूकता अभियान और फाइनेंसिंग सहायता देगा। MSMEs को बिजली बिल में 40-50% बचत होगी, साथ ही सरकारी सब्सिडी और लो-इंटरेस्ट लोन मिलेंगे।

टाटा पावर के सीईओ प्रवीर सिन्हा ने कहा, यह साझेदारी MSMEs को सस्ती और साफ ऊर्जा उपलब्ध कराएगी, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। बंगाल चैंबर के प्रेसिडेंट ने कहा कि राज्य में 48 लाख MSMEs हैं, जो GDP का 30% योगदान देते हैं। सोलर अपनाने से कार्बन उत्सर्जन कम होगा और रोजगार सृजित होंगे।

यह पहल PM सूर्य घर योजना और राज्य की रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी से जुड़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पश्चिम बंगाल रिन्यूएबल एनर्जी हब बनेगा। टाटा पावर के शेयर 1.5% चढ़े। यह कदम हरित अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा।





## Jindal Steel Plans to Double Structural Steel Capacity at Raigarh Plant

### Rs 5,000 Cr Investment to Lift Output to 2 MTPA by 2028; Targets Infrastructure Boom and Cost Leadership

**Raigarh:** Jindal Steel & Power Ltd (JSPL) has announced plans to double the structural steel production capacity at its Raigarh integrated steel plant in Chhattisgarh, taking it from the current 1 million tonnes per annum (MTPA) to 2 MTPA by 2028. The expansion, involving an investment of approximately Rs 5,000 crore, will position JSPL as India's largest structural steel producer.

The project includes upgrading hot rolling mills, adding advanced finishing lines, and enhancing value-added product capabilities like beams, columns, and channels used in high-rise buildings, bridges, and industrial structures. This expansion aligns with India's infrastructure surge and our focus on downstream value addition for better margins, said Bimlendra Jha, Managing Director, JSPL.

Raigarh, already JSPL's flagship facility with 5.6 MTPA crude steel capacity, benefits from captive iron ore and power, ensuring cost competitiveness. The structural steel segment, growing at 12-15% annually on the back of urbanisation and projects like Bharatmala and smart cities, offers higher margins. Analysts estimate the expansion could add Rs 3,000 crore to annual revenue by FY29, with EBITDA

margins improving 200-300 bps. Shares of JSPL rose 2.5% to Rs 1,050 on BSE, reflecting optimism. As India targets \$1 trillion infrastructure spending by 2030, JSPL's move strengthens its role in nation-building while driving sustainable growth through efficient, low-carbon steel production.



## Top queries related to Health Insurance

What are different types of health insurance?

What is Maternity, OPD, Ayurvedic/Homeopathy (AYUSH) cover?

What is a Network Hospital?

How many claims can I make?

Which is the best health insurance?

What is cashless treatment?

**If your question is on this list**

**just reply and get all your answers, free of charge**



**Vision Invest Tech Private Limited**

ARN: 10613 | AMFI Registered Mutual Fund Distributor

📞 (+91)7389912025 ✉ visionadvisorymkt@gmail.com



## Christmas is over

but you can still be your own Santa

Retire with **financial independence** by stepping up your SIP.

Start with ₹10,000/month & increase by 10% every year

This way, **₹10,000/month** can grow to around **₹8 Crore** in 30 Years

Assumed returns @12%. Figures are approximate and rounded off for simplicity.



**I can help you build your retirement corpus**

Mutual Fund investments are subject to market risks. Please read the documents carefully before investing.



**Vision Invest Tech Private Limited**

ARN: 10613 | AMFI Registered Mutual Fund Distributor

📞 (+91)7389912025 ✉ visionadvisorymkt@gmail.com





## December GST Collections Surge 6.1% to Cross Rs 1.74 Lakh Crore

### Robust Revenue Growth Despite Tax Cuts; Imports Drive 19% Jump, Reflecting Festive Demand and Economic Resilience

**New Delhi:** India's Goods and Services Tax (GST) collections in December 2025 rose 6.1% year-on-year to exceed Rs 1.74 lakh crore, marking the third consecutive month above Rs 1.7 lakh crore and signalling sustained economic momentum despite recent rate rationalisations.

The finance ministry attributed the uptick to strong festive season consumption, improved compliance, and a sharp 19% increase in revenues from imports. Domestic transactions contributed a steady 5% growth, while cess collections added to the kitty. Gross GST mop-up stood at Rs 1.74 lakh crore, with CGST at Rs 35,000 crore, SGST at Rs 36,000 crore, IGST at Rs 90,000 crore (including Rs 45,000 crore from imports), and cess at Rs 13,000 crore.

This consistent performance, even post rate cuts on 47 items in September, underscores the buoyancy in consumption and formalisation, a ministry official said. Refunds issued were Rs 22,000 crore, resulting in net collections of Rs 1.52 lakh crore up 8% YoY.

The surge aligns with 7.8% GDP growth in Q2 FY26 and robust indicators like PMI and e-waybills. States like Maharashtra, ,



Gujarat and Karnataka led contributions, while imports of electronics and gold fuelled IGST.

Experts view the data positively for FY26 revenue targets of Rs 22 lakh crore gross GST. Stable collections amid reforms indicate maturing tax administration, said an EY India analyst. With January typically strong due to advance tax, the trajectory bodes well for fiscal consolidation.

## RBI Sees Banks' NPAs Dropping to 1.9% by March 2027

### Baseline Scenario Projects Improvement from 2.1% in Sept 2025; Stress Tests Show Resilience Even Under Adverse Conditions

**Mumbai:** The Reserve Bank of India (RBI) has projected a further improvement in banks' asset quality, with the gross non-performing assets (GNPA) ratio expected to decline to 1.9% by March 2027 under the baseline scenario, according to its latest Financial Stability Report released on Tuesday.

As of September 2025, the GNPA ratio stood at a multi-decade low of 2.1%, down from higher levels in previous years, reflecting sustained recoveries, write-offs, and prudent lending. "The aggregate GNPA ratio of 46 banks may improve from 2.1% in September 2025 to 1.9% in March 2027 under the baseline scenario," the report stated. However, under medium and severe stress scenarios, it could rise to 3.2% and 4.2%, respectively.



Macro stress tests affirmed the banking system's resilience, with the capital to risk-weighted assets ratio (CRAR) projected at 16.8% by March 2027 (from 17.1% in September 2025) under baseline, remaining above regulatory minima even in adverse cases. No bank is expected to breach minimum capital requirements.

The report highlighted robust earnings, low slippages (0.7% half-yearly), and declining large borrower NPAs (33.8% share despite 44% credit exposure). Public sector banks led asset quality gains.

RBI Governor Sanjay Malhotra emphasized the system's strength amid global uncertainties, supported by strong macroeconomic fundamentals. Analysts view the outlook positively, expecting continued credit growth and margin stability.

As India aims for sustained 7%+ growth, the improving NPA trajectory bolsters confidence in the banking sector's role in economic expansion.



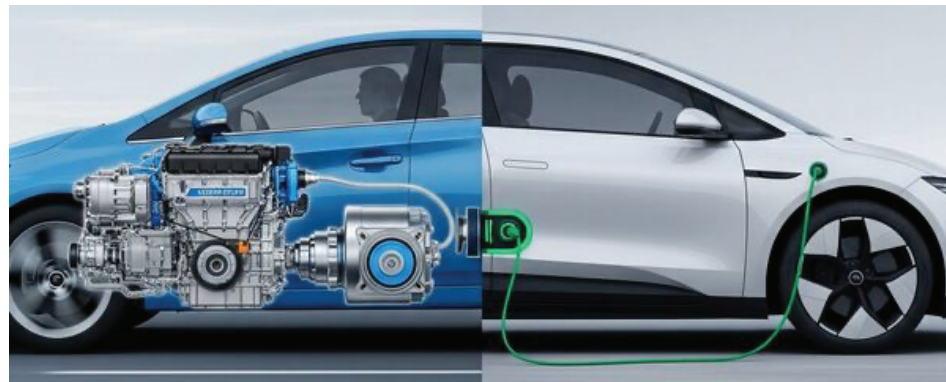
## Top Auto Firms Bag Rs 2,000 Cr PLI Incentives for EV Push

### Tata Motors, Mahindra Lead Recipients; Scheme Boosts Domestic Manufacturing and Exports Amid 8% Sector Growth

**New Delhi:** Leading automobile manufacturers, including Tata Motors and Mahindra & Mahindra, have received over Rs 2,000 crore in incentives under the Production Linked Incentive (PLI) scheme for advanced automotive technology, marking a significant boost to India's electric vehicle (EV) ecosystem. The Ministry of Heavy Industries disbursed the funds for FY24 performance, rewarding certified sales of eligible advanced automotive technology (AAT) products like EVs and components. Tata Motors topped the list with substantial payouts for its Nexon and Punch EV models, while Mahindra secured incentives for XUV400 and e-Verito. Other beneficiaries include Hyundai, Kia, and Ola Electric for two-wheelers and components.

This disbursement validates the scheme's success in driving domestic value addition and exports," said a ministry official. Launched in 2021 with Rs 25,938 crore outlay over five years, the PLI has spurred Rs 65,000 crore in investments and created 1.5 lakh jobs. Approved firms must achieve 50% domestic value addition to qualify.

The incentives 5-18% of sales value have accelerated EV



adoption, with certified sales crossing 1 lakh units in FY24. India's auto sector grew 8% in 2025, with EVs contributing 8% of passenger vehicles.

Analysts hail the payouts as timely amid global supply chain shifts, positioning India as an EV export hub targeting \$50 billion by 2030. However, delays in earlier disbursements had drawn criticism. With Rs 10,000 crore committed so far, the scheme eyes full utilisation by FY27, fostering self-reliance in batteries, motors, and power electronics.

## Hyundai Raises Vehicle Prices from January 1, 2026

### Up to 2% Hike Across Models to Offset Rising Input Costs; Creta, Venue, and Exter See Maximum Increases Amid Strong Demand

**New Delhi:** Hyundai Motor India Ltd (HMIL) has announced a price increase of up to 2% across its entire model range, effective January 1, 2026. The revision, impacting popular SUVs like Creta, Venue, Exter, and sedans such as Verna and Aura, aims to offset escalating input costs, including raw materials, logistics, and compliance expenses.

In a regulatory filing, HMIL stated the hike ranging from Rs 10,000 to Rs 50,000 depending on variants reflects sustained inflationary pressures despite operational efficiencies. We have absorbed costs for as long as possible to minimise impact on customers," said Tarun Garg, COO, HMIL. The company assured no further revisions in the near term.



Hyundai's decision follows similar moves by rivals Maruti Suzuki and Tata Motors, who raised prices by 1-4% citing commodity inflation. India's passenger vehicle market grew 8% in 2025, with Hyundai securing second spot at 14% share, driven by SUVs contributing 65% of sales.

The timing coincides with robust festive bookings and inventory normalisation post-supply chain disruptions. Analysts expect minimal demand dent, given pent-up rural recovery and wedding season momentum. Hyundai's EV lineup, including Ioniq 5 and upcoming Creta Electric, remains unaffected for now.

Shares of Hyundai Motor India traded flat at Rs 1,850 on BSE amid broader market caution. With input costs like steel and semiconductors stabilising globally, the industry hopes 2026 brings margin relief. As India targets 10 million annual PV sales by 2030, calibrated pricing remains key to balancing growth and affordability.



## जोमैटो-ब्लिंकिट ने 31 दिसंबर को रिकॉर्ड 75 लाख ऑर्डर डिलीवर किए: दीपिंदर गोयल

न्यू ईयर ईव पर सबसे व्यस्त दिन, पिछले साल से 25% अधिक ऑर्डर; फूड डिलीवरी और क्लिक कॉमर्स में नया कीर्तिमान

**नई दिल्ली:** फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो और उसकी क्लिक कॉमर्स इकाई ब्लिंकिट ने 31 दिसंबर 2025 को रिकॉर्ड 75 लाख ऑर्डर डिलीवर किए। जोमैटो के संस्थापक और सीईओ दीपिंदर गोयल ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की। उन्होंने इसे कंपनी का "सबसे व्यस्त दिन" बताया, जो पिछले साल के न्यू ईयर ईव से 25% अधिक है।

गोयल ने लिखा, 31 दिसंबर को जोमैटो और ब्लिंकिट ने मिलकर 75 लाख ऑर्डर डिलीवर किए। यह हमारे डिलीवरी पार्टनर्स और रेस्तरां के मेहनत का नतीजा है। इस दिन फूड ऑर्डर के साथ-साथ ग्रॉसरी, स्नेक्स और पार्टी आइटम्स की मांग चरम पर थी। ब्लिंकिट ने 10-15 मिनट डिलीवरी से ग्राहकों को आकर्षित किया।

यह रिकॉर्ड त्योहारी सीजन की मजबूत मांग को दर्शाता है। जोमैटो का GOV (ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू) इस दिन 500 करोड़ रुपये पार कर गया। कंपनी ने 2 लाख से अधिक डिलीवरी पार्टनर्स को बोनस और इंसेंटिव दिए। गोयल ने कहा कि 2026 में और तेज ग्रोथ की उम्मीद है, जिसमें ब्लिंकिट का योगदान प्रमुख होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि क्लिक कॉमर्स बाजार 2026 में 50,000 करोड़ रुपये पार करेगा। जोमैटो की मार्केट शेयर 55% से अधिक है। यह सफलता डिजिटल इंडिया और युवा उपभोक्ताओं की बदलती आदतों को दर्शाती है। शेयर बाजार में जोमैटो के शेयर 2% चढ़े। यह रिकॉर्ड कंपनी के लिए नई ऊंचाई का प्रतीक है।

शेयर बाजार में बायोकॉन के शेयर 3% चढ़े। यह कदम सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में बड़ा कदम है।

blinkit

zomato

## दवा कंपनियों को GMP अनुपालन के लिए अतिरिक्त समय: मंत्रालय राज्यों से कर रहा बातचीत

### छोटी-मध्यम इकाइयों को राहत, 2026 की डेडलाइन में छूट संभव; गुणवत्ता बनाए रखते हुए उत्पादन बाधित न हो

**जयपुर:** केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय छोटी और मध्यम दवा कंपनियों को गुड मैनुफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (GMP) अनुपालन के लिए अतिरिक्त समय देने पर विचार कर रहा है। मंत्रालय विभिन्न राज्यों से बातचीत कर रहा है, ताकि कुछ कंपनियों को 2026 की सख्त डेडलाइन में छूट मिल सके। यह कदम उन इकाइयों के लिए राहत लेकर आएगा, जो तकनीकी और वित्तीय चुनौतियों से जूझ रही हैं।

GMP नियमों का संशोधित शेड्यूल (Revised Schedule M) 2024 से लागू है, जिसमें सभी दवा निर्माताओं को विश्व स्तरीय मानकों का पालन करना अनिवार्य है। बड़ी कंपनियां तैयार हैं, लेकिन MSME सेगमेंट में 10,000 से अधिक इकाइयां अभी पिछड़ रही हैं। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हम गुणवत्ता से समझौता नहीं करेंगे,

लेकिन उत्पादन बाधित न हो और दवाओं की उपलब्धता प्रभावित न हो, इसके लिए लचीलापन दिखाया जा रहा है।

राज्यों जैसे गुजरात, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना से फीडबैक लिया जा रहा है, जहां दवा उद्योग केंद्रित है। उद्योग संगठनों ने मांग की है कि छोटी इकाइयों को 1-2 वर्ष की मोहलत मिले, साथ ही सब्सिडी और तकनीकी सहायता दी जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि सख्ती जरूरी है, क्योंकि घटिया दवाओं से स्वास्थ्य जोखिम बढ़ता है, लेकिन अचानक बंदी से दवा संकट हो सकता है।

यह बातचीत भारत को वैश्विक फार्मा हब बनाने की दिशा में संतुलित कदम है। मंत्रालय जल्द दिशानिर्देश जारी करेगा।



MPBL/2013/48052  
INVESTMENT AVENUES®  
(इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज)  
(A Publication of Vision Invest Tech Pvt. Ltd.)

## INVESTMENT AVENUES CALL FOR ARTICLES

Share Your Knowledge with  
INVESTMENT AVENUES

We invite individual, professionals, and  
entrepreneurs to contribute their  
expertise and experiences.

- STOCK MARKET
- MUTUAL FUNDS
- REAL ESTATE
- STARTUPS & ENTREPRENEURSHIP

### Guidelines:

1. Article must be original
2. Submit in MS Word format
3. Length should not exceed 500 words

[editor@investmentavenues.in](mailto:editor@investmentavenues.in)

write with us, inspire others, and make  
your voice heard in the world of investments!

## INVESTMENT AVENUES®

### Looking To Invest In Real Properties & Valued Businesses In Bhopal

Discover genuine real estate and well-assessed business  
opportunities — safe-to-invest and growth-oriented.

Secure Deals. Smart Investments.



EMAIL: [INVESTMENTAVENUES90@GMAIL.COM](mailto:INVESTMENTAVENUES90@GMAIL.COM)  
CONTACT: +91 73899 26586



## मारिको को Q3 में डबल-डिजिट लाभ वृद्धि की उम्मीद

## ग्रामीण मांग में सुधार और प्रीमियम प्रोडक्ट्स से बूस्ट; FY26 में 15% राजस्व ग्रोथ का लक्ष्य

मुंबई: एफएमसीजी दिग्गज मारिको लिमिटेड को तीसरी तिमाही (Q3 FY26) में डबल-डिजिट लाभ वृद्धि की मजबूत उम्मीद है। कंपनी के सीएफओ पवन अग्रवाल ने निवेशकों से कहा कि ग्रामीण मांग में सुधार, प्रीमियम ब्रांड्स की बिक्री बढ़ती और लागत नियंत्रण से लाभ में 12-15% की वृद्धि संभव है। यह अनुमान त्योहारी सीजन की मजबूत बिक्री और निर्यात में उछाल पर आधारित है।

मारिको के प्रमुख ब्रांड्स जैसे पैराशूट ऑयल, सफोला और वैल्यू एडेड हेयर ऑयल ने Q3 में 10-12% वॉल्यूम ग्रोथ दर्ज की। ग्रामीण बाजार, जो कंपनी के राजस्व का 35% योगदान देता है, में MNREGA और अच्छी फसल से मांग बढ़ी है। प्रीमियम सेगमेंट जैसे बी द ऑर्गेनिक और टू एलिमेंट्स ने 20% से अधिक ग्रोथ दिखाई। अग्रवाल ने कहा, हमारा फोकस प्रीमियमाइजेशन और डिजिटल चैनल्स पर है, जिससे मार्जिन सुधरेगा।

Q2 में कंपनी का लाभ 18% बढ़कर 450 करोड़ रुपये हो गया था। FY26 में 15% राजस्व वृद्धि का लक्ष्य है। मारिको ने बांग्लादेश और मध्य पूर्व में निर्यात बढ़ाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि FMCG सेक्टर में मारिको की स्थिति मजबूत है, खासकर हेल्थ और वेलनेस ट्रेंड से। शेयर बाजार में मारिको के शेयर 2% चढ़े। यह उम्मीद सेक्टर में सकारात्मक संकेत देती है।



## L&amp;T Secures Major Orders Worth Rs 5,000-10,000 Cr in Minerals &amp; Metals

## Contracts from SAIL and Others for Steel Plant Expansions; Reinforces Leadership in Domestic Metals EPC

Mumbai: Larsen & Toubro (L&T) has kicked off the new year with a strong order win, bagging major contracts valued between Rs 5,000 crore and Rs 10,000 crore from Steel Authority of India Limited (SAIL) and other clients in the domestic metals sector. The orders, secured by L&T's Minerals & Metals (M&M) business vertical, involve engineering, procurement, and construction (EPC) projects as well as specialised products.

Key highlights include capacity expansion at SAIL's IISCO Steel Plant in Burnpur, West Bengal, from 2.5 MTPA to 6.5 MTPA crude steel, and establishment of Sinter Plant 2 at Bokaro Steel Plant. These initiatives support SAIL's ambitious growth plans amid rising domestic steel demand.

This partnership with SAIL, spanning decades, continues to advance India's steel ecosystem through innovation and sustainable development, L&T stated in a regulatory filing. The M&M vertical has been on a winning streak, contributing significantly to the company's Rs 5 lakh crore-plus order book.

L&T's expertise in metallurgical projects positions it favourably for India's steel capacity target of 300 MTPA by 2030. The orders underscore the group's focus on high-value, integrated solutions in a sector growing at 8-10% annually.

Shares of L&T rose 1.5% to Rs 4,050 on BSE, reflecting investor enthusiasm. With a robust pipeline in infrastructure, hydrocarbon, and renewables, L&T is well-poised for 20% revenue growth in FY26, analysts say.



## अडानी ग्रीन एनर्जी ने 307.4 MW नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स चालू किए

कच्छ में 250 MW सोलर और अन्य विंड प्रोजेक्ट्स, कुल ऑपरेशनल क्षमता 12.5 GW पार; 2030 तक 45 GW लक्ष्य की दिशा में मजबूत कदम

अहमदाबाद: अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) ने गुजरात और अन्य राज्यों में 307.4 MW नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स का कमीशनिंग पूरा कर लिया है। इनमें कच्छ के विशाल रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में 250 MW सोलर क्षमता प्रमुख है, जबकि शेष विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं। कंपनी ने मंगलवार को बीएसई फाइलिंग में इसकी जानकारी दी, जिससे उसकी कुल ऑपरेशनल क्षमता 12.5 GW पार हो गई है।

AGEL के सीईओ अशिश खन्ना ने कहा, ये प्रोजेक्ट्स भारत की स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षा को मजबूत करेंगे। हमारी पाइपलाइन मजबूत है और हम 2030 तक 45 GW क्षमता का लक्ष्य हासिल करेंगे। कच्छ पार्क, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है, अब 5 GW से अधिक क्षमता वाला हो गया है। ये प्रोजेक्ट्स सोलर और विंड हाइब्रिड मॉडल पर आधारित हैं, जो ग्रिड स्थिरता बढ़ाते हैं।

यह कमीशनिंग C&I (कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल) और यूटिलिटी स्केल सेगमेंट में हुई है। AGEL की कुल पोर्टफोलियो अब 27 GW से अधिक है, जिसमें 12.5 GW ऑपरेशनल और शेष निर्माणाधीन है। कंपनी ने FY26 में 5 GW जोड़ने का लक्ष्य रखा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत के 500 GW नॉन-फॉसिल लक्ष्य (2030) को गति देगा। यह उपलब्धि हरित ऊर्जा क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान है।



Disclaimer: This content is for educational purposes only. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.